भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1507

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

बिहार में बाढ़ प्रबंधन हेतु परियोजना

1507. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामप्रीत मंडल:
श्रीमती लवली आनंद:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई व्यापक परियोजना तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार राज्य सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से 1300 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार ने भी नेपाल सरकार के सहयोग से ऊंचे बांध बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और मार्च, 2026 तक आगे बढ़ाया गया। ग्यारहवीं योजना से लेकर आज तक एफएमपी घटक के तहत बिहार को कुल 1624 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया कि हाल ही में राज्य ने बिहार की गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों पर लगभग 6198.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कुल 21 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की हैं।

राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने दिनांक 20.01.2025 को बिहार सरकार के वित्त विभाग से बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 1122.64 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की है।

(ग) और (घ): दिसंबर, 1991 में, भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (जिसे अब सप्त-कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया है) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संयुक्त रूप से तैयार करने के लिए सहमति बनी थी। विस्तृत जांच/ कार्य क्षेत्र तैयार करने और एक संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए अगस्त 2004 में नेपाल के विराट नगर में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय - सप्त-कोसी सन-कोसी जांच (जेपीओ-एसकेएसकेआई) की स्थापना की गई थी। जेपीओ-एसकेएसकेआई ने स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, निर्माण सामग्री सर्वेक्षण, भूकंपीय अध्ययन आदि से संबंधित क्षेत्रीय कार्य पूरा कर लिया है। डीपीआर तैयार करने से संबंधित कार्यों की प्रगति की निगरानी दोनों देशों के स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से की जाती है।

*****